

We have yet to wait to know the exact assistance and aid or loan that we might get, but, during the course of the next few months, it might be possible to consider the suggestion made by the hon. Member.

Shri S. C. Samanta: May I know whether it is a fact that when Government could not supply specific allotments demanded by the States they supply an excess of other categories and, if so, whether those items of other categories go to the market and the small-scale industries have to pay a higher price?

Shri Lal Bahadur Shastri: I want to inform the hon. Member that we do not want to supply unwanted steel to the State Governments or to the industry. But as there has been an acute shortage of supply of steel, we have sometimes to supply them steel which was not in accordance with their needs or requirements. For example, the Russian steel which had come to this country had to be supplied to various State Governments. It has to be fabricated according to the needs of the industry concerned. So, the State Governments or the industries have to make a special effort or even have to undergo some difficulty in order to meet their needs in the present difficult circumstances.

सूती वस्त्र उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

+

*१५६०. { श्री पद्म देव :
श्री वाजपेयी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १६ अप्रैल, १९५८ के अतिरिक्त प्रश्न संख्या २४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड ने इस बीच क्या प्रगति की है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : बोर्ड न अब तक बम्बई, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और कलकत्ता में सम्बन्धित

पक्षों के बयान लिखे हैं। देश के दूसरे कपड़ा उद्योग केन्द्रों में भी बोर्ड जायेगा।

An Hon. Member: It may be read in English also.

Mr. Speaker: Yes.

Shri Abid Ali: The Board has so far heard the parties at Bombay, Kanpur, Delhi, Ahmedabad and Calcutta. It has still to visit a number of textile centres in India.

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकेंगे कि यह काम कब तक खत्म हो जायेगा ?

श्री आबिद अली : अभी यह कहना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सी जगहों पर बोर्ड को जाना है और सम्बन्धित पक्षों से बातचीत करनी है, उसके बाद वह उस पर विचार करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट बनायेगा। अभी उसका अंदाजा देना मुश्किल है।

Shri Tangamani: This Textile Wage Board under Shri Jheejibhoj was appointed more than two years ago. May we know at least now whether this report will be before us at the end of this year at least?

Shri Abid Ali: This Board was not appointed two years back. It was appointed on 30th March, 1957. I have just replied to the previous question that it is difficult, at this stage, to give any indication of the time by which we will receive the report, because too much work has to be done. In this Board both workers' and employers' representatives have been appointed. So they have to hurry up.

श्री रा० क० वर्मा : क्या श्रीमान्, को यह ज्ञात है जैसा कि उन्होंने फरमाया कि वेज बोर्ड, बम्बई, कानपुर, दिल्ली और अहमदाबाद वगैरह गया था, बम्बई और अहमदाबाद में जब वेज बोर्ड गया तो कम्युनिस्ट्स समर्थित यूनियन की तरफ से वेज बोर्ड के सामने कोई वडेंस देने नहीं आया ?

श्री आशिष बराली : इस बारे में मैंने एक भ्रमखार में तो पढ़ा था लेकिन बोर्ड की तरफ से मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं मिली ।

श्री रा० क० वर्मा : क्या श्रीमान्, को यह ज्ञात है कि वेज बोर्ड ने सम्बन्धित उद्योगपतियों और ट्रेड यूनियनों से सितम्बर १९५७ के अन्त तक प्रश्नावली के उत्तर में मेमोरेडम मांगा था लेकिन कम्प्युनिस्ट्स समर्थित टैक्सटाइल फ़डरेशन की तरफ से अभी तक उनकी प्रश्नावली के उत्तर में उनका मेमोरेडम न आने से वेज बोर्ड को कार्यवाही करने में देरी हुई ?

श्री आशिष बराली : मैं फिर वही अज्ञं करूंगा कि इस क्रिसम की कुछ चीजें बम्बईके एक भ्रमखार में मैंने देखी थी । भ्रम भ्रगर उमकी तफ़सील माननीय सदस्य को चाहिये तो वे उमके लिये नोटिस दे और मैं उसको बोर्ड से मंगा कर पेश कर दूंगा ।

Shri Dasappa: In view of fact that the Government have appointed three Wage Boards already—apart from one for textiles, they have appointed Wage Boards for sugar as well as for the cement industry—and in view of the fact that many things are common like the rise in the cost of living index and so on, may I know what arrangements are made for integrating the work so far as the ascertainment of these facts is concerned?

Shri Abid Ali: A suggestion was made that the Chairman of these three Boards may meet and again a suggestion was also made that all the members of the Wage Boards may meet together, and this was forwarded to the respective Wage Boards.

श्री रा० क० वर्मा : क्या श्रीमान् को यह ज्ञात है कि कपड़ा उद्योग के संचालकों द्वारा मौजूदा कथित क्राएसिस को बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करने के कारण वेज बोर्ड के कार्य में भी विघ्न पैदा हो रहा है ?

श्री आशिष बराली : वेज बोर्ड का यह ख्याल तो है कि जो कपड़े की कामत है और जो उद्योग की हालत है वह बहुत अच्छी नहीं है और इस काम को क्रोरन कर लेने से शायद वह जो पहले उन्होंने समय का ख्याल किया था, उस नतीजे तक नहीं पहुंच सके और इसलिए कुछ धीरे धीरे जाने का विचार है ।

श्री रा० क० वर्मा : श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है.....

Mr. Speaker: I cannot allow the hon. Member to go on talking like this.

श्री रा० क० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक छोटो सा सवाल है । वेज बोर्ड का ख्याल ऐसा बनाने की गरज से ही इस उद्योग के संचालकों ने प्रलत तौर से इस क्राएसिस का प्रचार किया है ।

श्री आशिष बराली : मेरे लिये यह कहना तो मुश्किल होगा ।

Shri Tangamani: May I know whether, in view of this delay of 18 months, the Government will give directions to the Wage Boards that they will come out with an interim award before the end of this year?

Shri Abid Ali: It is for the workers' representatives to make this suggestion there, and we will forward this suggestion also to the Wage Board.

Shrimati Sucheta Kripalani: Just now the hon. Minister said that the members of the Wage Board are deliberately slowing up the progress of the work for certain reasons. May I know whether the Government also agree with those reasons or whether the Government are willing to take some steps to see that the work of the Wage Board is expedited?

Shri Abid Ali: That was not my intention.